epaper
हिन्दुस्तान

केंद्रीय करों और शुल्क से यूपी को 1.46 लाख करोड़ मिलेंगे

आम बजट पेश किए जाने के दौरान लखनऊ में मंगलवार को खूब उत्सुकता दिखी। एलईडी पर बजट की खबरें देखते लोग।

02/02/2022

लखनऊ | हेमंत श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश

एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार को केंद्रीय करों व शुल्क से 1,46,498.76 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस धनराशि के मिलने से राज्य सरकार अपनी योजनाओं व खर्चों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकेगी। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के मुकाबले 12,514.5 करोड़ रुपये अधिक है।

सबसे अधिक सेंट्रल जीएसटी से बन रही है राज्य की हिस्सेदारी : 2022-23 में केंद्रीय करों में राज्य सरकार का शेयर 17.939 तय है। कोरोना महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों में आर्थिक व कारोबारी गतिविधियां बेहतर चल रही हैं, जिसकी वजह से करों व शुल्क में वृद्धि नजर आ रही है। केंद्रीय करों में राज्य के निर्धारित हिस्से के लिहाज से राज्य को कारपोरेट टैक्स के मद से 45,742.47 करोड़ रुपये, इनकम टैक्स से 44,177.57 करोड़ रुपये, सेंट्रल जीएसटी से 48,103.07 करोड़ रुपये, कस्टम ड्यूटी से 6,351.68 करोड़ रुपये, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 1,978.49 करोड़ रुपये और सेवा कर से 147.11 करोड़ रुपये मिलेंगे। इन सबका योग 1,46,498.76 करोड़ रुपये बनता है। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय करों व शुल्क से राज्य सरकार को कुल 1,33,984.26 करोड़ रुपये मिलने हैं। 2020-21 में इस मद में राज्य सरकार को कुल 1,10,426.40 करोड़ रुपये मिले थे। यहां बता दें कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कुल केंद्रीय करों व शुल्क में से 41 फीसदी हिस्सेदारी राज्यों की होती है। इस 41 फीसदी में सबसे बड़ा शेयर उत्तर प्रदेश का होता है।